

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No 10580/2023 Shri Anup Rajendra Singh Somwanshi, Partner, THAKUR STONE CRUSHER, Village-Chikaldara, District Amrawati (MH), Prior Environment Clearance for Jhallar Crusher Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (20318 cum per year) (Khasra 10/2), Village-Jhallar, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) (DEIAA to SEIAA)**

प्रकरण समिति की पूर्व 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 का प्रस्तुतीकरण हुआ था। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

12. Water requirement (KLD):

13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:

15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप राजेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में श्री शैलेश सिकरवार के नाम से पत्र क्रमांक 127 दिनांक 30/06/2017 द्वारा डिया से ई. सी. जारी हुई थी। यह खदान नवीन परियोजन प्रस्तावक श्री अनूप राजेन्द्र सिंह सोमवंशी को अंतरण (अंतरण आदेश 366 दिनांक 24/02/2023) हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खदान क्षेत्र छोटी पहाड़ी पर स्थित है एवं लीज क्षेत्र में से 05 वर्ष तक खनन कार्य हो चुका है और अभी तक 7500 घन मीटर उत्पादन लिया जा चुका है।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई के समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन अपूर्ण पाया गया :—

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

- डिया की शर्तों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 45 पौधों को लगाने का प्रावधान था उसका पालन प्रतिवेदन देखा गया व बैरियर जोन में पर वृक्षारोपण में नहीं देखा गया।
- बैरियर जोन में 7.50 मी. पर वृक्षारोपण पूर्व शर्तों के आधार पर रोपण नहीं पाया गया।
- समाजिक कार्य प्रस्तुत किया गया व फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये।
- माईनिंग प्लान में पूर्व उत्खनित क्षेत्र दिखाया गया है।
- ईसी में वर्णित शर्त क्रमांक 09 –11 के पुष्टी के पश्चात ही भू प्रवेश की अनुमति दी जावेगी
- माईनिंग प्लान के वर्षवार प्रोडक्शन मैप में X-X' पर खनिज उपलब्धता की स्थिति दर्शायी गयी है,
- अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति का हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में निम्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावेगा।
- खदान के दक्षिण दिशा में एक पक्की रोड लीज एरिया से लगी हुई है तथा एक अन्य पक्का रोड 150 मी. की दूरी पर है।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- डिया की शर्तों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 45 पौधों को लगाने का प्रावधान था जो कि बैरियर जोन में पर वृक्षारोपण में नहीं देखा गया। अतः 03 माह के अंदर बैरियर जोन में वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- खदान क्षेत्र से जो पूर्व में ओवर वर्डन निकल चुका है उसकी मात्रा एवं भविष्य में खदान क्षेत्र में जो ओवर वर्डन निकलेगा इनका प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- माईनिंग प्लान में Y-Y' एक्सेस पर स्थिति नहीं दर्शायी गयी है, अतः Y-Y' एक्सेस खनिज उपलब्धता की स्थिति दर्शायी जायें।
- खदान के दक्षिण दिशा में एक पक्की रोड लीज एरिया से लगी हुई है तथा एक अन्य पक्का रोड 150 मी. की दूरी पर है, अतः आवश्यक सेटबैक छोड़ते हुये पुनर्रक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें।
- माईनिंग प्लान में पूर्व उत्खनित क्षेत्र दिखाया गया है यदि खनन में कोई संशोधन होता है तो पुनर्रक्षित संशोधन प्लान प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले घटकों के लिये कार्बन फुट प्रिंट प्रस्तुत किया जावे।
- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक एवं पर्यावरण के अनुरूप क्षेत्र में कार्य किया जावे व ईएमपी/सीआर में भी प्रस्तुत किया जावे।

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

**2. Case No 10647/2023 Shri Sabapathy Arumugam, Authorized Person, M/s Afcons Infrastructure Private Limited, Afcon House, 16, Shah Industrial State, Veera Desai Road, Azad Nagar, Andheri West, District-Mumbai (MH)-400053, Prior Environment Clearance for Ghusiya Mal Crusher Stone Quarry in an area of 3.95 ha. (85000 cum per year) (Khasra No. 368/1, 368/2, 370), Village-Ghusiya, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP). T.P.-for 05 Yeras**

प्रकरण समिति की पूर्व की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे:-

1. यदि अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति का हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में निम्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
2. यदि खदान पेसा क्षेत्र में स्थित हो तो पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें।
  - पशु/जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर फेंसिंग लगाने हेतु प्रस्ताव दें। तदनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।
  - स्वाइल प्रोफाईल परीक्षण हेतु 4 से 5 पिट्स बनाने थे, जो प्रस्तुत नहीं किये जा सकें। उपरोक्त कार्य पूर्ण कर तदनुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करें।
  - क्षेत्र की जियो-हाईड्रोलॉजिकल अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया।
  - क्षेत्र की टॉप स्वाइल आंकलन हेतु की गई गणना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है अतः पुनर्गणना कर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Sabapathy Arumugam, Authorized Person ऑनलाईन, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा) लि. नोयडा (उ.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी की समीक्षा की गई। अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति का हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार को निर्देश दिये कि कलेक्टर से विधिवत आदेश जारी करवा लिये जावें। खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में टावर-लगभग 218 मी., आबादी उत्तर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में क्रमशः 460 एवं 354 मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रस्तुत बिन्दु संतोष जनक पाये गये।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-

- ग्राम क्षेत्र के भू-जल स्रोतों का अध्ययन कर क्षेत्र के भू-जल स्तर का डेटा प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार सीईआर योजना में पालक शिक्षक संघ के खाते में 03 माह के भीतर प्रस्तावित राशि जमा किये जाने का प्रस्ताव ।

### **3. Case No 10142/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Lalpur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Lalpura, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (MP)**

पूर्व में यह प्रकरण समिति की पूर्व की 667वीं बैठक दिनांक 08/8/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई थी।

#### **प्रकरण का परीक्षण :-**

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है जबकि खनन योजना में रिवर वेड माईनिंग दर्शायी गई है। अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक परियोजना

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा का पत्र क्रमांक 1565 दिनांक 20/11/2023 के माध्यम से खनिज निरीक्षक का मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि अवगत कराया कि उक्त स्वीकृत रेत खदान खोदू-भरू नहीं होकर नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वीकृत है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कोर्डिनेट भी प्रस्तुत किये गये। समिति ने संबंधित परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी को निर्देश दिये कि अतिरिक्त कोर्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.19 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि   | राशि(रु. में) |
|---|---------------|
| ग्राम ग्राम लालपुरा के आंगनवाड़ी केंद्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जायेगा | 40,000        |

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

| कं. | वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान  | पौधों की प्रजातियाँ   | मात्रा (संख्या में) |
|-----|---|---|---------------------|
| 1   | नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार | खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ । | 800                 |
| 2   | गांव के पंचायत भवन , आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय                      | आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य                                   | 800                 |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   | विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे                                       | स्थानीय फलदार प्रजातिया   |      |
| 3   | आस पास के गांवों में वितरित-पौधे की ऊंचाई) किया जाना (मीटर 1 न्यूनतम | आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां लगाई जाएगी | 3200 |
| <p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p> |  |   |      |

**4. Case No 10143/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Kayatkedi Sand Quarry in an area of 1.20 ha. (10008 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kayat khedi, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)**

पूर्व में यह प्रकरण प्रकरण समिति की पूर्व की 667वीं बैठक दिनांक 08/8/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई थी।

**प्रकरण का परीक्षण :-**

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि पूर्णतः जलमग्न है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदान अंक्षास एवं देशांस त्रुटिपूर्ण है अतः इनका पुनरीक्षित अंक्षास एवं देशांस पुनः प्रस्तुत किये जायेगे। अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके तकनीकी रूप से पुनरीक्षित अंक्षास एवं देशांस के साथ जियोटेग

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

फोटोग्राफ के साथ स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा का पत्र क्रमांक 1556 दिनांक 10/11/2023 के माध्यम से खनिज निरीक्षक का मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि अवगत कराया कि उक्त स्वीकृत रेत खदान खोदू-भरू नहीं होकर नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वीकृत है तथा खदान क्षेत्र में वर्तमान में पानी भरा हुआ है जिसमें विगत कई वर्षों से पानी भरा हुआ है जिसे खदान का संचालन किया जाना संभव नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वीकृत है, जोकि पानी डूबा हुआ है एवं खनिज अधिकारी के पत्र अनुसार भी खदान क्षेत्र में विगत कई वर्षों से पानी भरा हुआ है, अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है ।

**5. Case No 10146/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.024 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)**

पूर्व में यह प्रकरण समिति की पूर्व की 667वीं बैठक दिनांक 08/8/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई थी ।

**प्रकरण का परीक्षण :-**

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है जबकि खनन योजना में रिवर वेड माईनिंग दर्शायी गई है । अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा का पत्र क्रमांक 1554 दिनांक 10/11/2023 के माध्यम से खनिज निरीक्षक का मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि अवगत कराया कि उक्त स्वीकृत रेत खदान खोदू-भरू नहीं होकर नर्मदा नदी क्षेत्र में स्वीकृत है तथा खदान क्षेत्र में वर्तमान में पानी भरा हुआ है।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-

1. खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर खदान क्षेत्र के 03 वर्षों का उत्पादक विवरण प्रस्तुत करें।
2. खनिज अधिकारी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें कि मार्च एवं अप्रैल माह में नदी खदान क्षेत्र में पानी रहता है अथवा नहीं?

**6. Case No 10124/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Katghada Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 175), Village- Katgarha, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP) B-2.**

प्रकरण समिति की पूर्व की 667वीं बैठक दिनांक 08/8/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

### प्रकरण का परीक्षण :-

- प्रस्तुतीकरण के दौरान यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र में से एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज प्रस्तावित है एवं पर्यावरण स्वीकृति 05 वर्ष के लिये होगी अतः जिला खनिज अधिकारी संबंधित विभाग से निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज के संबंध में जानकारी प्राप्त करे की निर्माण एवं पूर्ण समाप्ति जानकारी प्रस्तुत करे। तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा का पत्र क्रमांक 1558 दिनांक 10/11/2023 के माध्यम से खनिज निरीक्षक का मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि रेत खदान स्थल पर वर्तमान में नेशनल हाईवे ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना पाया गया। जिससे की मौके पर रेत खदान में खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। जिससे की उक्त रेत खदान को स्वीकृत रेत खदान की सूची से पृथक किया जाना उचित होगा। अतः पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खनिज अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण का पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

**7. Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)**

प्रकरण आज सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

**8. Case No 10343/2023 M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd., Vijan Mahal Hotel Road, Tilheri, Tehsil and District Jabalpur (MP)-482002, Prior Environment Clearance for Expansion Hotel Project "Vijan Mahal" located at Khasra No. 107/1 (old), New No. 107/2, (Includes 107/26 & 107/27), 107/10, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 at Village - Tilheri, Tehsil & District Jabalpur (MP).Query Reply.**

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion Hotel Project "Vijan Mahal" located at Khasra No. 107/1 (old), New No. 107/2, (Includes 107/26 & 107/27), 107/10, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 at Village - Tilheri, Tehsil & District Jabalpur (MP).

Earlier this case was in the 679<sup>th</sup> SEAC dated 14.09.2023. After presentation committee observed following information is to be submitted / revised by PP.

1. Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print .

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

2. PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
3. Use of sewerage water provision for flushing and gardening.
4. Proposer's contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
5. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
6. Calculate vehicles movement numbers which shall include Aganwadies, nursing homes, School etc.
7. For indoor air quality the ventilation provisions shall be made in few rooms as per National Building Code of India.
8. Green area is proposed as 24.95% with podium 53 % hence proposed revised plantation scheme & species of green area as suggested by the committee.
9. Revised the CER scheme as suggested by the committee.

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 679<sup>th</sup> SEAC, dated 14.09.2023.

The query reply was presented by PP Shri Sandeep from M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd. Jabalpur and their Env Consultant Ms. Dimpal Tomar, FAE from M/s. Vibrant Techno Lab Private Limited, Jaipur, (Rajasthan).

After presentation asked PP to submit following clarification about the project:-

- Furnish revised details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print as suggested by the committee.
- Revised STP cost and power generation through solar energy shall be re-calculated and cost shall be added in the EMP.
- Re-calculated number of vehicles, occupying space in terms of ECS & Parking.
- Provision of basic facilities like wash rooms and toilets in each towers for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided to avoid open defecation in the nearby areas.
- The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.
- Looking to the use of e-vehicles hence appropriate number of battery charging points per towers shall be provided.
- Revised plantation species as suggested by the committee.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

**9. Case No 10613/2023 Shri Tanish Yadav, Project Proponent, H.No. 33, Ward No. 22, Dinesh Ganj (Daru Godam), Sendhwa, District-Barwani (MP)-451666, Prior Environment Clearance for Shahpura Stone Quarry in an area of 3.62 ha. (24700 cum per year) (Khasra No. 3/1/1/1/1/1/2, 3/1/9, 3/1/10), Village-Shahpura, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP)**

प्रकरण समिति की पूर्व की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज के आधार पर समिति ने पाया कि दक्षिण दिशा में खदान के पास आबादी दिख रही है। अतः इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई है:-

- खदान के दक्षिण दिशा के समीप आबादी दिख रही है अतः इस संबंध में राजस्व विभाग/खनिज विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणिक जानकारी एवं तदनुसार सेटबैक दर्शाते हुये सर्फेस प्रस्तुत करेंगे।
- खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए वर्ष-वार प्रोडक्शन मेप।
- पुनरिक्षित वृक्षारोपण योजना।
- खदान क्षेत्र की स्वाइल प्रोफाईल।
- पुनरिक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के दक्षिण दिशा के समीप आबादी दिख रही है अतः इस संबंध में तहसीलदार का पत्र क्रमांक 7496 दिनांक 20/11/2023 प्रस्तुत किया गया पत्र में उल्लेख है कि हल्का पटवारी एवं आवेदक के शपथ पत्र के अनुसार भूमि के दक्षिण पूर्व में 44 मी. की दूरी पर एक खाली मकान (टपरा) है, जो माईन ओनर द्वारा समान रखने हेतु उपयोग किया जावेगा एवं खदान के दक्षिण पश्चिम में 27 मी. की दूरी पर एक खाली शेड बना हुआ है। माईन ओनर द्वारा चौकिदार रखने के उपयोग हेतु किया जा रहा है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 24,700 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष होगी।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रु. 07.21 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.12 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि  | राशि (रु. में) |
|--|----------------|
| ग्राम शाहपुरा के माध्यमिक शाला में 3 महीने के भीतर सी एस आर के तहत सहयोग राशि प्रदान करना। | Rs.1,00,000/-  |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान  | पौधों की प्रजातियाँ   | मात्रा (संख्या में) |
|-------|--|---|---------------------|
| 1     | बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण , तथा खदान के चारो ओर गारलैंड ड्रेन में सागौन , नीम तथा अन्य बीज वाले पौधों का रोपण किया जायेगा । | नीम, करंज , सफेद कस्तर व स्थानीय प्रजाति आदि।               | 1086                |
| 2     | आवागमन सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण ।  | सिस्सू ,काला सिरस , नीम , करंज , अर्जुन, चिरोल, अशोक आदि।   | 1086                |
| 3     | शाहपुरा स्कूल एवं ग्राम पंचायत के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण ।   | नीम,करंज, सिस्सू एवं स्थानीय प्रजातियां।                    | 1086                |
| 4     | शाहपुरा, नदयाबाद एवं गोंडी ग्रामवासियों को पौधों का वितरण  | आम, मुनगा, जामुन, अमरुद, कटहल, आंवला व स्थानीय प्रजाति आदि। | 1242                |

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

**10. Case No 9632/2023 Shri Jaivinder Singh Bhatia, M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., 509-510, Princess Business Sky Park, Opposite Orbit Mall, A.B. Road, Vijay Nagar, Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Proposed Capacity Expansion of Grain Based Distillery from 40 KLD to 190 KLD distillery along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 hectares. in (Khasra No. - 15, 17) at Village-Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist. Khargone, MP Cat. – 5(g) Distillery Project. EIA-PPT**

This is case of Prior Environment Clearance for proposed Capacity expansion of grain based distillery from 40 KLD to 190 KLD distillery along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 ha. in Khasra No. 15, 17 at Village-Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist.-Khargone, M.P. Cat. 5(g),

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 624<sup>th</sup> SEAC Meeting dated 26/02/23 wherein ToR was recommended.

The EIA was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and authorized representatives Shri Ritesh Singh Tomer on behalf of PP Shri Jaivinder Singh Bhatia from M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., Barwaha. During presentation PP submitted that it is an expansion in the existing Grain Based Distillery for production of RS/ENA & 5.6 MW Cogeneration power plant.

**The salient features of the project are as given below:-**

|    |                         |   |                       |
|----|-------------------------|---|-----------------------|
|    | Proposal /Activity Name | Shri Jaivinder Singh Bhatia, M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., 509-510, Princess Business Sky Park, Opposite Orbit Mall, A.B. Road, Vijay Nagar, Indore (MP)-452010, Email-agrawaldistillery@rediffmail.com, Phone-917314249491.  |                       |
| 1. | Location of Project     | <i>Prior Environment Clearance for Proposed Capacity Expansion of Grain Based Distillery from 40 KLD to 190 KLD along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 ha. at Khasra No. - 15, 17 Village-Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist. Khargone, MP [411737] Cat. – 5(g) Distillery Project.</i> |                       |
| 2. | EC (Fresh or Exp.)      | Expansion.  |                       |
| 3. | Previous EC Details     | <b>MPSEIAA Case No. – 3059/2015,</b><br>EC Issued vide letter No. 4739/SEIAA/2016 dated 13.12.16  |                       |
| 4. | Proposed ToR            | ToR Recommended in 624 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 26/02/23.   |                       |
| 5. | Project Cost            | Existing : 8010 Lakh, Proposed: 22015 Lakh, Total: 30025 Lakh,  | As per Point no.- 6.3 |
| 6. | Project Location        | At Village - Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist. Khargone, (M.P.).   |                       |

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

|                            |  |   |                                   |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 7.                         | Area in ha.                                  | Plot area: 7.6330 Ha.   |                                   |
| 8.                         | Product & Production Capacity                | <i>Proposed Capacity Expansion of Grain Based Distillery from 40 KLD/Year to 150 KLD/Year.</i>  |                                   |
| 9.                         | CGWA / Gram Sabha NOC                        |   | As per Privesh Form Point No. -2. |
| 10.                        | Range of ground water table (post monsoon)   | (m bgl)   | (Form -2 Point no. - 14.6),       |
| <b>Documentary Details</b> |  |   |                                   |
| 11.                        | Gram Sabha / Gram Panchayat NOC - DN Dated . |   |                                   |
| 12.                        | Env. Con.                                    | Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 09/08/ 2024.   |                                   |
| 13.                        | CTO/CTE                                      | Outward No: 116087,27/07/2022, Consent No:AWH-56373, Dt. 27/07/2022.<br><br><b><u>Product &amp; Production Capacity:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Co-Gen Power Plant 1.500 MWH</li> <li>Country liquor/IMFL bottling 360000.000 NOS Cases/Year</li> <li>Indian made foreign liquor bottling 1200000.000 NOS Cases/Year</li> <li>Rectified Spirit /ENA 13200.000 KL/Year (40 KLD)</li> </ul> |                                   |
| 14.                        | Consent Status                               | Validity of latest consent (Valid up to) 30-06-2027.  |                                   |

In the SEAC 693th meeting dated 20.10.2023 after presentation the committee asked PP to submit following information:

- 1- Revised plantation schenme of previous and proposed plantation to be furnished including proposal of plantation of Khus Grass along the adjeacent nalla with 03-05 rows and proposal for Miyawalki Plantation as suggested by the committee.
- 2- The compliance of previous EMP & CSR cost coul't be furnished with expenditure incurred .
- 3- All compliances of previous EC and CTO shall be furnished.
- 4- Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot-print.
- 5- Revised the CER scheme as suggested by the committee, the proposal should include
  - Skill development,
  - Infrastructure development in the veterinary Hospital,
  - Toilet construction in the nearby Aganwadi etc.
- 6- Year wise production data along with raw material procurement for last 05 years duly certified by the Excise department.
- 7- Proposal for enhancement of the use of solar power in utilities.
- 8- Coloured lay-out map distingusing the existing plant and the proposed expansion.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the SEAC 693th meeting dated 20.10.2023.

The query reply was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP Shri Jaivinder Singh Bhatia from M/s Agrawal Distilleries Pvt. Ltd., Barwaha. wherein PP submitted that M/s Agrawal Distilleries Pvt ltd has proposed an expansion in production capacity of its existing grain-based distillery at Khasra No. – 15 and 17, Village- Sabalpura, Tehsil Barwaha, District-Khargone (M.P.). from 40 KLD to 190 KLD distillery along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 hectares.

**Chronology of the project:**

| Sr. No | Progress  | Date       |
|--------|---|------------|
| 1.     | Acceptance of Form-I along with Proposed ToR to the SEIAA | 20.01.2023 |
| 2.     | Presentation of ToR to SEAC                               | 26.02.2023 |
| 3.     | ToR issued  | 29.03.2023 |
| 4.     | Draft EIA Report submission to the MPPCB                  | 01.05.2023 |
| 5.     | Public Hearing  | 04.07.2023 |
| 6.     | Final EIA Report submission to SEIAA                      | 29.09.2023 |
| 7.     | EIA Presentation to SEAC                                  | 20.10.2023 |
| 8.     | ADS Presentation to SEAC                                  | 15.12.2023 |

After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for **Proposed Capacity Expansion of Grain Based Distillery from 40 KLD to 190 KLD distillery along with 5.6 MW Power Plant in an area of 7.633 hectares. in (Khasra No. - 15, 17) at Village-Sabalpura, Tehsil-Barwaha, Dist. Khargone, MP Cat. – 5(g) Distillery Project.,** subject to the special conditions:

**(A) Statutory compliance:**

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

(Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).

2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if any tree falling is to be carried out.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

### **(B) Air quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.
4. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. DG exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
6. CO<sub>2</sub> generated from the process shall be bottled/made solid ice and sold to authorized vendors.
7. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
8. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

### **(C) Water quality monitoring and preservation**

1. Total fresh water requirement shall not exceed 1140 cum/day proposed to be met from Ground Water.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

2. Spent Wash/stillage shall be sent to the decanter followed by the Multiple Effect Evaporator and dryer to form DDGS. DDGS to be used as cattle feed. The MEE & Drier condensate, spent lees, WTP Rejects, Boiler & Cooling tower blowdowns, washings etc. shall be treated in the 'Condensate Polishing Unit' (CPU). STP shall be installed to treat domestic wastewater. The plant will be based on 'Zero Liquid Discharge' system and no effluent/treated water will be discharged outside factory premises
3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable), the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
4. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
5. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
6. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
7. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
8. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

**(D) Noise monitoring and prevention**

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

**(E) Energy Conservation measures**

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

2. Possibility of installation of solar power system may be explored.

**(F) Waste management**

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon etc. shall be directly sent to CTSDf, Dhar.
3. The Fly ash generated from boiler shall be stored in silos and utilized in onsite brick manufacturing plant.
4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
6. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. The company shall undertake waste minimization measures as below:
  - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

- b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
- c. Use of automated filling to minimize spillage.
- d. Use of Close Feed system into batch reactors.
- e. Venting equipment through vapour recovery system.
- f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

**(G) Green Belt**

- 1. 1.70hact will be covered with the good green belt and 4250 trees will be planted.
- 2. PP shall plantation of Khus Grass along the adjacent Nallah with 03-05 rows.
- 3. The green belt of 5m width will be developed mainly along the periphery and road side by Miyawaki Plantation. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
- 4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
- 5. PP shall plantation of Khus Grass along the adjacent Nallah with 03-05 rows.
- 6. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat.

**(H) Safety, Public hearing and Human health issues**

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

### (I) EMP& Corporate Environment Responsibility

1. The proposed EMP cost is Rs. 2955.00 Lakhs as capital and 295.50 Lakhs /year as recurring cost.
2. Under CER activity, Rs. 175.00 Lakhs has proposed for different activities. PP shall comply with the commitment as follows:

| S.No. | DETAILS   | Total Cost in Lakhs | No of Year | Year wise implementation and Budgetary provision during Operation phase |          |          |
|-------|---|---------------------|------------|---|----------|----------|
|       |   |                     |            | 1st year  | 2nd year | 3rd year |
| 1.    | Ambulance donation in Govt. Hospital Kasrawd  | 20                  | 1          | 20  | -        | -        |
| 2.    | Infrastructure development of nearby Govt Schools (Khamkheda, Laundi) (Building renovation, Furniture & safe drinking water (RO) distribution ) | 20                  | 3          | 7.5   | 7.5      | 5        |
| 3.    | Uniform, Table, Chairs, Computers & Sports kit Distribution in nearby Govt School (Kadwaliya, Jagatpura, Lakhanpura)                            | 20                  | 3          | 7.5   | 7.5      | 5        |
| 4.    | Medical camp-skin, Dental, Heart, Eye   | 20                  | 3          | 7.5   | 7.5      | 5        |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

|    |   |            |   |             |             |           |
|----|---|------------|---|-------------|-------------|-----------|
|    | checking & Specs distribution   |            |   |             |             |           |
| 5. | Infrastructure development of veterinary hospital Barwaha                     | 25         | 3 | 9           | 8           | 8         |
| 6. | Skill Development with the help of ITI, Barwaha (50% Male & 50% Female)       | 15         | 3 | 5           | 5           | 5         |
| 7. | Tree plantation in PHcKasrawad  | 5          | 1 | 5           | -           | -         |
| 8. | Approach Road, Site tree Plantation and Road Repairing (Factory to Kadwaliya) | 35         | 3 | 15          | 10          | 10        |
| 9. | Construction of Toilet in the nearby Anganwadi's                              | 15         | 3 | 5           | 5           | 5         |
|    | <b>Total</b>  | <b>175</b> |   | <b>81.5</b> | <b>50.5</b> | <b>43</b> |

3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

**J. Miscellaneous**

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**11. Case No 9114/2022 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.416 ha. (45,000 cum per annum) (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)**

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

प्रकरण समिति की पूर्व की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि बेंच का निर्माण एवं खनन् योजना को भौमिकी एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय प्रमुख जबलपुर द्वारा अनुमोदित किया गया है। खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए जो वर्ष-वार प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत किया गया, उसके फीचर लीजेन्ड से मिलान नहीं करते अतः परीक्षण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं :-

1. सर्फेस प्लान के इंडेक्स में भिन्नता है। अतः खदान की संरचना के दृष्टिगत बेंच की लम्बाई एवं चौड़ाई दर्शाते हुए वर्ष-वार प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
2. समिति के द्वारा सुझाये गये अनुसार कलस्टर मैनेजमेंट प्लान।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया। खदान क्षेत्र के आसपास कुल 08 खदानें हैं, जिसके लिये प्रारम्भिक राशि रुपये 75 लाख एवं आगामी अवधि के लिये रुपये 16 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी होगी। इस संबंध में समिति का सुझाव है कि उपरोक्त 08 खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि डीएमएफ खातों में जमा की जावेगी। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जा सकता है। जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे। माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान की कम्प्लाइन्स रिपोर्ट तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 45,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष होगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रु. 75 लाख में से जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित अंश एवं रिक्रिंग राशि रु. 16 लाख प्रति वर्ष जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित अंश डीएमएफ मद में जमा करेंगे।



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

3. परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान की कम्पलाईन्स रिपोर्ट तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र माईनिंग अधिकारी से प्राप्त कर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि  | राशि (रु. में) |
|--|----------------|
| ग्राम प्रकाश बम्हौरी मे 01 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी। | 50,000 / -     |
| ग्राम प्रकाश बम्हौरी के शासकीय विद्यालय मे 01 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी।                          | 40,000 / -     |

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

| कं.   | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान             | पौधों की प्रजातियाँ  | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|--|---------------------|
| 1   | बैरियर जोन शासकीय भूमि खसरा नंबर (1901)             | शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ। | 942                 |
| 2   | बैरियर जोन निजी भूमि खसरा नंबर (1935,1937,1938)     | बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा इत्यादि।                      |                     |
| 3   | प्रकाश बम्हौरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में      | कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर इत्यादि।                  | 20                  |
| 4   | गाँव प्रकाश बम्हौरी, के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा इत्यादि।                      | 388                 |
| 5   | अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु              | नीम, पीपल, सेमल, पुत्रंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।                         | 350                 |
| उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। |   |  |                     |

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

### **12. Case No 9970/2023 Shri Yogendra Tomar, Lease Owner, R/o A/131, Ward-22, Phase-3, SPM Colony, District-Hoshangabad (MP)-461001, Prior Environment Clearance for Rampura Chikaldi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 42/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)**

प्रकरण समिति की पूर्व की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे:-

- प्रस्तावित खदान निजी भूमि पर आवंटित है ।
- प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिसके संरक्षण हेतु स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर लगभग 0.76 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है ।
- डी.जी.एम. कार्यालय से रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य करने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
- क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे ।

समिति ने परीक्षण उपरांत पुनः परियोजना प्रस्तावक से प्राकृतिक नाला के संबंध में स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ना दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस प्लॉन, प्रोडक्शन प्लॉन एवं पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

योगेन्द्र तोमर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान का भू-स्वामित्व परियोजना प्रस्तावक के नाम पर है।** रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य करने का अनुमोदन पत्र (डिजीटल) दिनांक 18/10/2023 को प्राप्त कर लिया गया है। **परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पक्का रोड** , प्राकृतिक नाला के संबंध में 1.10 हे. क्षेत्र एवं सेप्टी जोन के संबंध में 0.140 हे. गैर खनन क्षेत्र/ संरक्षण हेतु छोड़ा गया है अतः स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर लगभग 0.76 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है, जोकि सरफेस मेप में दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 22,800 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष होगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.23 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि   | राशि (रु. में) |
|---|----------------|
| ग्राम रमपुरा चकल्दी में एक नया हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा | 60,000/-       |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ  | मात्रा (संख्या में) |
|-----|---|--|---------------------|
| 1   | बैरियर जोन                              | बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा, सागोन और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ। | 630                 |
| 3   | परिवहन मार्ग                            | नीम, आम पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा,   | 70                  |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
|   |   | मौलश्री, इत्यादि।  |      |
| 4   | रमपुरा चकल्दी ग्रामवासियों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, रुद्राक्ष, सीता अशोक मुनगा इत्यादि। | 1680 |
| 5   | शासकीय विद्यालय रमपुरा चकल्दी में         | कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मौलश्री, गुलमोहर इत्यादि।         | 20   |
| उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये।<br>गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे। |   |  |      |

**13. Case No 10303/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 1.84 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2842/2), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)**

प्रकरण आज सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

**14. Case No 10302/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)**

प्रकरण आज सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

**15. Case No 10273/2023 Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s Trimurti Enterprises, 190, Ajaybag Colony, District-Indore (MP)-452001 Prior Environment Clearance for Pipalkhut Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 13/5), Village- Pipal Khut, Tehsil-Mhow, District-Indore (M.P.) (DEIAA to SEIAA)**

प्रकरण आज सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

**16. Case No 10476/2023 Shri Ramnik Patel, Lease Owner, 18, Power House Road, Alot, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Kamalkheda Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19000 cum per year) (Khasra No. 533), Village- Kamalkhera, Tehsil-Petlawad, District-Jhabua (MP)**

प्रस्तुत प्रकरण समिति की पूर्व की 688वीं बैठक दिनांक 12/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। बैठक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र दिनांक 22/11/2017 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री रामनिक पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. जारी हुई थी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- खदान क्षेत्र में ओवर वर्डन डम्प पाये गये अतः इनका प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र के ढाल को विचार करते हुये सेटलिंग टैंक की संख्या निर्धारित करते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

- खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 81 मी. व उत्तर दिशा में 397 मी. पर प्राकृतिक नाला स्थित है अतः आवश्यक सेटबैक देते हुये सरफेस मैप में प्रस्तुत करें।
- खदान एरिया की फेन्सिंग की कुल लंबाई कितनी है और अभी तक कितनी फेन्सिंग कर ली गई है एवं फेन्सिंग कार्य कब तक पूर्ण करेंगे पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र का भू-जल स्तर के डेटा प्रस्तुत करें।
- पुनरक्षित कार्बन फूट प्रिंट के ऑकड़े प्रस्तुत करें।

### **17. Case No 9935/2023 Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, R/o Plot No. 50 to 54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur, District-Dhar Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP) (EIA Presentation)**

This is a case received for the Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP). The project falls under the Cat 5 (f) (Synthetic Organic Chemicals Industry). ToR for carrying out EIA / EMP was recommended in 652<sup>nd</sup> SEAC Meeting dated 14/06/2022. EIA was received on-line for appraisal. Environment Consultant Shri Pradeep & Shri Shubham, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) and the proponent presented the EIA / EMP before the committee in the meeting. The salient features of the project as per the submissions made by the PP and their consultant are as follows:

| SN  | Projects Details        |   | Remarks |
|-----|-------------------------|---|---------|
| 15. | Online Proposal No      | SIA/MP/IND3/440545/2023   |         |
| 16. | Proposal /Activity Name | <b>Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, R/o Plot No. 50 to 54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775, E-mail-hprath@macleodspharma.com, Mobile-7292350605</b> |         |
| 17. | Location of Project     | <i>Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP) <b>Cat 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Industry.</b></i>        |         |
| 18. | ToR details             | ToR Recommended in 652 <sup>nd</sup> SEAC Meeting dated 14/06/2022.   |         |
| 19. | Description of Project  | M/s Macleods Pharmaceuticals Limited is currently engaged in Formulation of capsules and tablets (Non-EC Product) at Plot No  |         |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            |  | M-50 to M-54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur Dist. Dhar. Now Macleods Pharmaceuticals Limited proposing to manufacture Oncology bulk drugs & Peptide based bulk drugs, for which prior environment clearance has to be taken. |
| 20.                        | Water Supply Agreement                             | dated 29/04/2019.   |
| 21.                        | DFO NOC letter                                     | PP Apply letter No. Nil dated 10/04/2023.   |
| 22.                        | Inter State distance letter                        | PP Apply letter No. Nil dated 18/04/2023.   |
| 23.                        | CEPI Status  | PP Apply letter No. Nil dated 18/04/2023.   |
| 24.                        | Production Qty.                                    | As per Parivesh Portal uploaded Form.   |
| 25.                        | Range of ground water table (post monsoon) (m bgl) | (Form -2 Point no. -14.6),  |
| <b>Documentary Details</b> |  |   |
| 26.                        | Env. Con.  | Shri Pradeep Chandasna & Shri Shubham, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.)   |
| 27.                        | Water /Air Consent                                 | Valid up to dt. 31/01/2024.   |
| 28.                        | PFR  | Ok  |
| 29.                        | Risc Assessment                                    | -   |
| 30.                        | Any tree cutting proposed is observed              | No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -  |
| 31.                        | Google image status:                               |   |

In the 691<sup>st</sup> SEAC Meeting dated 18/10/2023 after deliberations the committee has sought following information along with the supporting documents from the PP & their consultant :

1. Copies of the all CTOs' (including the renewed CTOs') issued by the MPPCB for the existing products along with report on compliances of the terms and conditions of the CTO submitted to MPPCB.
2. Current generation of effluent and sewage with water balance.
3. Carbon foot-prints – current and that expected after expansion.
4. Revised plantation scheme covering the entire boundary with proposal of planting Khas-grass in 2-3 rows along the river/nallah.
5. Revised water balance clearly showing the volume to be re-used, re-cycled etc.
6. Use of CNG instead of coal / bio-briquetts shall be explored and reported with final proposal on fuel to be used.
7. Proposal for Solar power generation / use shall be enhanced to 30% of the total power requirement in the industry.
8. CER activities to be revised including the remote & tribal villages as beneficiary.



**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal on dated 28.11.2023, which was asked by the 691<sup>st</sup> SEAC Meeting dated 18/10/2023.

The quarry reply was presented by Shri Shbham Dubey Env. Consultant from M/s. Envisolve and PP Shri Vikas Kushwaha Deputy Manager before the committee PP submitted -

- CTO copies issued by MPPCB along with compliance of the terms and conditions were presented.
- Details of revised current water Balance, generation of effluent and sewage with water balance.
- Carbon foot-prints—current and that expected after expansion.
- Revised Plantation scheme with coloured layout map.
- Commitment reg. Solar panels and use 30% of total power requirement from solar power.
- Revised CER activities.

and the same found satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Proposed Expansion in Existing Formulation Plant by M/s. Macleods Pharmaceuticals Limited at Plot No M-50 to M-54A, Indore Special Economic Zone, Phase - II, Pithampur Dist. Dhar., Cat. -5(f). with following products**

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Total Production Capacity</b> | <b>Existing -</b><br><b>Proposed –</b> | <b>1. Capsules 50 Cr. Nos/Year</b><br><b>2. Tablets- 144 Cr. Nos/Year</b><br><b>1. Oncology bulk drugs-2000 kg/year</b><br><b>2. Peptide-based bulk drugs -65 kg/ year</b> |
|----------------------------------|--|--|

Subject to the following special conditions:

**(A) Statutory compliance:**

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

### **(B) Air quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate this system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

| Sr. No | Boiler/ DG sets | Capacity                      | Stack Height (Meter) | APCM                                 |
|--------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1.     | Boiler          | 2 X 850 Kg/Hr each (existing) | 30                   | Bag Filter and Adequate stack height |
|        |                 | 3000Kg/Hr(existing)           |                      |                                      |
|        |                 | 600Kg/Hr(existing)            |                      |                                      |
|        |                 | 3000Kg/Hr(Proposed)           | 30                   |                                      |
| 2.     | DG              | 2x 1250 KVA each(existing)    | 30                   | Adequate Stack Height                |
|        |                 | 1010 KVA(Proposed)            | 30                   |                                      |
|        |                 | 1500 KVA(Proposed)            | 30                   |                                      |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
5. The DG sets (2x1250 kVA each existing)&(proposed 01x1010 kVA& 01x1500 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16<sup>th</sup> November, 2009 shall be complied with.

**(C) Water quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. “Zero Liquid Discharge” shall be ensured using ETP (125-KLD), RO(100-KLD), 10 KLD SEE and no waste/treated water shall be discharged outside the premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB’s server for remote operations.
3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
4. Total fresh water requirement shall not exceed 350 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, than CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
6. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.

7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

### **(D) Noise monitoring and prevention**

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (2x1250 kVA each existing) & (proposed 01x1010 kVA & 01x1500 kVA) for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

### **(E) Energy Conservation measures**

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 4500KVA.
3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

### **(F) Waste management**

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

| CAT.NO | Type of Waste              | Peptide (Annual Qty in MT) | Oncology (Annual Qty in MT) | Disposal Mode            |
|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 28.1   | Process Residue and wastes | 0.1                        | 0.8                         | Will be sent to the TSDF |

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

|             |  |   |     |                                     |
|-------------|--|---|-----|-------------------------------------|
| <b>28.2</b> | Spent catalyst   | NA  | 1   |                                     |
| <b>28.3</b> | Spent carbon   | NA  | 0.2 |                                     |
| <b>28.4</b> | Off specification products   | 0.5   | 0.5 |                                     |
| <b>28.5</b> | Date-expired products  | 0.2   | 0.3 |                                     |
| <b>35.3</b> | Chemical sludge from waste water treatment                                     | Existing- 200MTA<br>Proposed - 100 MTA<br>Total-300 MTA   |     |                                     |
| <b>28.6</b> | Spent solvents   | 430   | 15  | (Authorized Recycler)               |
| <b>5.1</b>  | Spent Oil  | Existing- 06 MTA<br>Proposed - 02 MTA<br>Total-08 MTA     |     | Will be sent to authorized recycler |
| <b>33.1</b> | Empty barrels/container s/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes | Existing- 50.00 MTA<br>Proposed - 50 MTA<br>Total-100 MTA |     | Will be sent authorized recycler    |
| <b>22.2</b> | HEPA Filter  | Proposed-0.2 MTA  |     | Will be sent to the TSDF            |

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

**(G) Green Belt**

1. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. 19 % Plantation already has been developed by PP. PP will develop total 33% green area. PP also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

**(H) Safety, Public hearing and Human health issues**

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

### **(I) EMP& Corporate Environment Responsibility**

1. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
2. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

3. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
4. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
5. The proposed EMP cost is Rs. 1064 lakhs and 82 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 14 lakhs and Rs. 50 lakhs is proposed for green belt development.
6. Under CER activity, capital cost is Rs. 95 lakhs proposed for different activities as mentioned below:

| Sr. No. | DETAILS   | Total Cost in Lakhs | No of Year | Year wise implementation and Budgetary provision during Operation phase (In Lakhs) |          |          |
|---------|---|---------------------|------------|--|----------|----------|
|         |   |                     |            | 1st year   | 2nd year | 3rd year |
| 1.      | Short term skill Development program's at tribal villages like Sulawat, Nalcha, Kamadpur&Hasalpur and more nearby villages. It should be accomplished through government ITI institutes. Also, PP will ensure that training batch formation considering equal ratio of male and female candidates.  | 35                  | 3          | 10   | 10       | 15       |
| 2.      | We will develop inhouse center of excellence (COE) for skill development of local candidates for employment generation also it will be part of Mukhya Mantri SikhoKamao Yojna (SKY). All CER cost will spent on students training and logging , food, logistics support , equipment's/instruments will be used in training program. No amount will be used on establishment of infrastructure | 60                  | 3          | 25   | 25       | 10       |



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

|  |  |           |  |           |           |           |
|--|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | for training centre.<br>Also , PP will ensure that training batch formation considering equal ratio of male and female candidates. |           |  |           |           |           |
|  | <b>Total</b>   | <b>95</b> |  | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>25</b> |

7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
8. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

### **X. Miscellaneous**

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 दिसम्बर 2023**

**18. Case No 10708/2023 Shri Pramod Kaplish, Lessee, R/o Plot No. 58/59, Shivalaya, Sankhedi, Kolar Road, Near Danish Kunj, District-Bhopal (MP)-462042, Prior Environment Clearance for Bamladad Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 89/1), Village-Bamaladad, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP). TOR**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद कपलेश एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण   | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज  |               |
|--|--|---------------|
| परियोजना प्रस्तावक,<br>परियोजना / कम्पनी का<br>नाम व पता | Shri PRAMOD KAPLISH, Lessee, Plot No. 58/59, Shivalaya Sankhedi, Kolar Road, Near Danish Kunj, Bhopal (M.P.)   |               |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल<br>(सरकारी/निजी)                     | 89/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)  | 4.00 hectare. |
| स्थल   | Village Bamladad, Tehsil Ichhawar, District Sehore (M.P.).   |               |
| लीज स्वीकृति   | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर पत्र क्रमांक 952 दिनांक 19/04/23 के द्वारा लीज अंतरित की गई ।  |               |
| श्रेणी (बी-1/बी-2)                                       | बी-2   |               |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर                                    | अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।   |               |
| डिया ई.सी. का विवरण<br>(यदि लागू हो)                     | डिया सिहोर के पत्र क्रमांक 611 दिनांक 31/05/18 के द्वारा पत्थर-22,230 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।  |               |
| नया/क्षमता विस्तार                                       | नया प्रोजेक्ट ।  |               |
| उत्पादन क्षमता   | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-60,000 घनमीटर/वर्ष है ।   |               |
| 500 मीटर की परिधि में<br>अन्य खदानें                     | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र पृ. क्रमांक 2661 दिनांक 18/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।   |               |
| वन मण्डलाधिकारी की<br>अनापत्ति                           | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र पृ. क्रमांक 2661 दिनांक 18/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । |               |
| तहसीलदार की अनापत्ति                                     | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र   |               |

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | पृ. क्रमांक 2661 दिनांक 18/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । |
| गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति  | उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 160मी. एक हालेज रोड लीज एरिया से लगी हुई है।<br>दक्षिण पूर्व दिशा— डैम लगभग 230मी.<br>पूर्व दिशा— आबादी 500 मी. से अधिक दूरी पर  |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-62 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है ।   |

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

- 1- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले घटकों के लिये कार्बन फुट प्रिंट प्रस्तुत किया जावे।
4. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

### **19. Case No 10709/2023 Shri Shyam Singh, Lessee, R/o Village-Kenwaha, Post-Veera, District-Shivpuri (MP)-473781, Prior Environment Clearance for Kenwaha Flag Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 245), Village-Kainwaha, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP) B-2.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Shyam Singh, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण  | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज   |
|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता              | Shri Shyam Singh, Lessee, R/o Village-Kenwaha, Post-Veera, District-Shivpuri (MP)-473781, Prior Environment Clearance for Kenwaha Flag Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5,000 cum per year) (Khasra No. - 245), Village-Kainwaha, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP) [446548]. |
| परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल  | खसरा नं.- 245, एरिया- 1.00 ha., निजि भूमि   |
| परियोजना स्थल   | ग्राम- केनवाहा, तहसील- पिछौर, जिला- शिवपुरी (म.प्र.).   |
| सैधातिक सहमति   | पत्र क्र0. 11000 दिनांक 18/08/2023.   |
| परियोजना की श्रेणी  | बी-2.   |
| जल/वायु सम्मति नवीनीकरण   | लागू नहीं ।   |
| खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर   | • The mining will be done without blasting with the help of stone cutter machine or Chisel & Hammer.  |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)                             | लागू नहीं ।   |
| उत्पादन क्षमता  | फ्लेग स्टोन - 5,000 मी <sup>3</sup> प्रति वर्ष ।  |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण । | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी  |

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

|   |  |
|---|--|
|   | के अंतर्गत आता है।   |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी                              | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।  |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी                                  | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 12/09/2023 अनुसार नहर-300 मी., पक्का रास्ता - 200 मी. तथा सूखा नाला - 50 मी. की दूरी पर स्थित है।   |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/  | ग्राम पंचायत- मऊकुडच्छा जिला - शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 01 दिनांक 10/02/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।   |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति                      | कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।  |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर पश्चिम दिशा- नदी.-90 meters- 10मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया है।  |
|   | दक्षिण पूर्व दिशा-Pucca road -75 meters 25मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया है।   |
|   | उत्तर- पूर्व दिशा- Habitation -308 meters  |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति                                  | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 12/09/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावेगा।<br>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर पश्चिम दिशा में नदी.- 90 meters एवं दक्षिण पूर्व दिशा-Pucca road -75 meters की दूरी पर स्थित है। अतः क्रमशः - 10मी. एवं 25मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया है। अतः खनन योग्य 0.5 हे. एरिया उपलब्ध होगा।

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **फलेग स्टोन** – 5000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.63 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि   | राशि (रु०. में) |
|---|-----------------|
| शासकीय प्राथमिक स्कूल डीडिपुरा में रंगाई पुताई फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी | 60,000          |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान                     | पौधों की प्रजातियाँ  | मात्रा (संख्या में) |
|-----|---|--|---------------------|
| 1   | बैरियर जोन  | नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ                    | 700                 |
| 2   | परिवहन मार्ग  | कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ | 100                 |
| 3   | शास. अंकुर योजना के तहत केनवाहा ग्रामवासियों में वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।     | 400                 |

**20. Case No 10710/2023 Shri Akhil Birthare, Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar, (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP).B-2.**

This is a case of Prior Environment Clearance Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) . The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by the Mr. Yamesh Sharma, Env. Consultant from M/s. EQMS India Pvt. Ltd. Delhi. along with PP's Shri Akhil Bilthare O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar. PP submitted following information about the project :-

- As per MoEF&CC EIA notification dated 14.8.2018, all irrigation projects with CCA > 2000 ha and < 10000 ha shall be treated as 'B2' and shall be apprised on the basis of EMP.
- Apchand Medium Irrigation project, proposed across Gadheri river a tributary of Sonar, shall be situated in Tehsil/Block Sagar, District Sagar.
- The project envisages construction of 520m long composite dam with maximum height of 19.50m; 60m long central ogee shaped spillway fitted with radial gates; 20m long non-overflow dam section on either side of spillway and 1395m long saddle dam, maximum height 13.54m.
- It is designed for gross and live storage of 20.93 MCM and 19.55 MCM respectively at FRL 461.50 masl for providing Rabi irrigation to command area of 4830 ha in 20 villages of draught prone Garhakota Tehsil, through a well-planned network of gravity mains and pipe irrigation network.
- **The total land requirement for project is 597.55 ha of which 181.39 ha shall be forest land; 55.75 ha shall be Government land and 360.41 ha shall be private land which is spread over 04 villages in Tehsil & District Sagar, Madhya Pradesh.**
- **The Forest Advisory Committee in its meeting held on 17.7.2023, recommended the proposal for diversion of 181.39 ha forest land for the construction of Apchand Medium Irrigation Project. Wildlife Clearance is not warranted in the present case.**

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

- Proposed irrigation under Rabi shall be 4830 ha which includes 3030 ha Wheat Hybrid (3MV) and 1800 ha Gram N2 respectively. The project is likely to be completed in time-frame of three years.
- About 21.36ha land shall be acquired temporarily for laying underground pipeline.
- No National Park, Sanctuary, Defense Establishments, Archaeological Monuments, Notified Eco- sensitive areas or protected area under Wild Life (Protection) Act exists within the project area or within 10 km distance from it.No archaeological monument of national importance lies either in the project area or in its submergence area. There is also no structure of national heritage in the area.
- Project site is located in Seismic Zone-III. The predominant land use class is agriculture land (54.69%), followed by dense forest (21.64%), open forest (19.89%), settlement (3.27%) and waterbody (0.51%).
- Based on monsoon runoff of 35 years (1982 to 2016) the 50% 75% and 90% dependability has been assessed as 34.6 MCM, 27.6MCM and 22.7 MCM respectively. The yield rate at 75% dependability is 0.24MCM/sq km.
- **Flora and Fauna:** In the study area 184 species of plants which include 62 tree species, 44 shrub species and 78 herbs/grasses/climbers were recorded. Forty-one economically important plant and twenty-twoimportant medicinal/ethnobotanical importance plant species were recorded. No RET species falling under IUCN Red List was recorded/reported from study area. The faunal study reveals that 15 mammalian species of which 4 species (Golden jackal, Indian crested porcupine, Sambar and Striped hyaena) belong to the schedule-I of Indian Wildlife Protection Act (1972), amended in 2022. Fifty-six avifauna species have been recorded /reported of which one (Indian Peafowl) belongs to Schedule-I. Eleven species of herpetofauna were recorded /reported of which three species (Russell's Viper,Cobra and Rat snake) belong to Schedule-I.

The project details submitted by PP on Parivesh Portal are given below:-

| SN | Information Required     | Details   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Project Name             | Shri Akhil Birthare, Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar, (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) [442654]. <b>Cat. - 1(c) River Valley Project.</b> |
| 2. | Activity details in CCA: | <b>CCA - 4830 Ha.</b>   |
| 3. | Nature of Land involved  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-Forest Land [A] - 416.18 Ha.</li> <li>• Forest Land [B] - 181.39 Ha.</li> </ul>  |



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

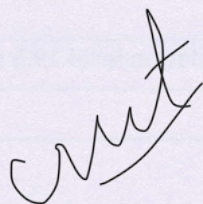
|     |  |   |                              |
|-----|--|---|------------------------------|
|     |  | • Total Land [A+B] - 597.55 Ha.   |                              |
| 4.  | Project Cost Rs.   | 16266.51 Lakhs.   |                              |
| 5.  | <b>Description of Project:</b><br>Apchand Medium Irrigation project, proposed across Gadheri river a tributary of Sonar, shall be situated in Tehsil/Block Sagar, District Sagar. The project envisages construction of 520 m long composite dam with maximum height of 19.50m; 60.00 m central ogee shaped spillway fitted with 10mx6m radial gates with crest level at El.455.50 masl; non-overflow dam section 20.00 m long on either side of spillway and 1395 m long saddle dam, maximum height 13.54m. It is designed for gross and live storage of 20.93 MCM and 19.55 MCM respectively at FRL 461.50 masl for providing Rabi irrigation to command area of 4830 ha (CCA) in 20 villages of draught prone Garhakota Tehsil, through a well-planned network of 7.5km long gravity mains and pipe irrigation network. Proposed irrigation under Rabi shall be 4830 ha which includes 3030 ha Wheat Hybrid (3MV) and 1800 ha Gram N2 respectively. The project is likely to be completed in time-frame of three years. The cost of project is Rs16266.51 lakhs only. |   |                              |
| 6.  | Forest Clearance details   | Proposal No.  | FP/MP/IRRIG/43200/2019.      |
|     |  | File No.  | 8-20/2022-FC                 |
|     |  | Date of approval  | 21/08/2023.                  |
|     |  | Area diverted/proposed to be diverted (in Ha)   | 181.39 Ha.                   |
|     |  | First Stage clearance F N 8 20 2022 -FC.pdf   | Uploaded on Parivesh Portal. |
| 7.  | Type of Dam  | Earthen   |                              |
| 8.  | Dam height   | Dam height from the deepest foundation level 19.5 mt.   |                              |
| 9.  | Length of the Dam (m)  | 445 mt.   |                              |
| 10. | River/River sub - basin/Basin  | Gadheri/ Ken/Yamuna.  |                              |
| 11. | Lat. Log.  | Latitude 23° 47'5.88" N<br>Longitude 78° 59'0.05" E   |                              |
| 12. | Green Belt   | EMP Proposed.   |                              |
| 13. | DFO NOC letter details   | Letter No. 971 dated 05/03/2021. (Distance 28 km)   |                              |
| 14. | PWD distance letter  | Letter No. 854 dated 16/02/2021 (Uttar Pradesh State distance - 76 Km.).                        |                              |
| 15. | EMP/ Env. Con  | M/s EQMS Global Pvt. Ltd. formerly known as EQMS India Pvt. Ltd. Delhi. Valid up to 11/11/2026. |                              |

After presentation the committee asked to PP to submit following clarification details for further consideration of the project:

1. Ecological damage study wrt flora and fauna and tree felling .
2. Soil conservation plan.
3. Calculate the Ecoservice System & its remediaton plan.

701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 दिसम्बर 2023

4. Catchment improvement plan.
5. Biodiversity conservation plan regarding flora & fauna, approved by the District Biodiversity Board.
6. Calculate the carbonfoot print include all componants.
7. Wild life conservation plan which shall be approved from district level authority as Schedule –I species are occurring in the project area.
8. To protect or minimization of seepage towards habitation side, hence management Plan shall be submitted .
9. The GoI's policy for benefit cost ratio shall be submitted.
10. Furnish total quantity of fertile top soil of farmer's agriculture fields shall be used.
11. Classification-wise land details of forest, private and revenue land.
12. Study shall be carried out from the competent agency to ascertain that the soil to be utilized for construction of dam is good quality or not?
13. Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
14. Need based CER scheme as suggested by the committee.
15. Muck disposal and management plan.



(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव



(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- ‘B’**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 15 दिसम्बर 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### Annexure- ‘C’

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.



## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 15 दिसम्बर 2023

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

#### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

## 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2023

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

# 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 15 दिसम्बर 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

**खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-**

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

| क्र. | स्थल  | ऊँचाई न्यूनतम   | गोलाई न्यूनतम |
|------|---|-----------------|---------------|
| 1.   | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र  | 02.5 – 03.0 फिट | 03–05 से. मी. |
| 2.   | रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी   | 03.5 – 05.5 फिट | 05–10 से.मी.  |
| 3.   | पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक । |                 |               |
| 4.   | आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद                        |                 |               |

# 701वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 15 दिसम्बर 2023

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ। | 1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर) |
| 2 | 4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)  | न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)                   |
| 3 | 6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)  | पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर  |

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि) | पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। |
| 2 | स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे   | 01 11.6 फीट   |
| 3 | चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।            | पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर                   |

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।